

**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194द की उपधारा (2) के अंतर्गत कठिनाइयों को दूर करने के लिए
दिशानिर्देश**

परिपत्र संख्या 12/2022 [एफ. संख्या 370142/27/2022-टीपीएल], दिनांक 16-6-2022

वित्त अधिनियम, 2022 ने आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) में 1 जुलाई 2022 से एक नई धारा 194द जोड़ी है।

नई धारा के अनुसार, कोई व्यक्ति, जो किसी निवासी को कोई लाभ या सुविधा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, उसे ऐसा लाभ या सुविधा प्रदान करने से पहले ऐसे लाभ या सुविधा के मूल्य या कुल मूल्य का 10% @ स्रोत पर कर काटना होगा। लाभ या सुविधा पैसे में परिवर्तनीय हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन ऐसे निवासी द्वारा व्यवसाय करने या किसी पेशे का अभ्यास करने से उत्पन्न होनी चाहिए।

यदि वित्तीय वर्ष के दौरान निवासी को प्रदान किए गए या प्रदान किए जाने वाले लाभ या सुविधा का मूल्य या कुल मूल्य बीस हजार रुपये से अधिक नहीं है, तो यह कटौती करने की आवश्यकता नहीं है।

कर कटौती की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति पर भी लागू नहीं होती है, जो एक व्यक्ति/हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) कटौतीकर्ता है, जिसका व्यवसाय से कुल बिक्री/सकल प्राप्तियां/सकल कारोबार एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, या पेशे से पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, उस वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान जिसमें उसके द्वारा ऐसा लाभ या अनुलाभ प्रदान किया गया है। अधिनियम की धारा 194द की उप-धारा (2) बोर्ड को केंद्र सरकार के अनुमोदन से कठिनाइयों को दूर करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने के लिए अधिकृत करती है। इन दिशानिर्देशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना आवश्यक है और ये आयकर अधिकारियों और लाभ या अनुलाभ प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए बाध्यकारी हैं।

तदनुसार, अधिनियम की धारा 194द की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, बोर्ड, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इसके द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करता है: -

दिशानिर्देश

प्रश्न 1. क्या यह आवश्यक है कि लाभ या अनुलाभ प्रदान करने वाले व्यक्ति को अधिनियम की धारा 194द के तहत कर काटने से पहले यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या वह राशि अधिनियम की धारा 28 के खंड (iv) के तहत कर योग्य है?

उत्तर: नहीं। कटौती करने वाले को यह जांचने की आवश्यकता नहीं है कि वह जो लाभ या अनुलाभ प्रदान कर रहा है, वह अधिनियम की धारा 28 के खंड (iv) के तहत प्राप्तकर्ता के हाथों में कर योग्य होगी या नहीं। यह राशि किसी अन्य धारा जैसे धारा 41(1) आदि के तहत कर योग्य हो सकती है। अधिनियम की धारा 194द किसी निवासी को कोई लाभ या अनुलाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर 10% की दर से स्रोत पर कर काटने का दायित्व डालती है। यह जांचने की कोई और आवश्यकता नहीं है कि प्राप्तकर्ता के हाथों में राशि कर योग्य है या नहीं या किस धारा के तहत यह कर योग्य है। इस संबंध में यह रेखांकित किया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 195 के संदर्भ में यह जानना आवश्यक है कि कटौतीकर्ता द्वारा किया गया भुगतान अनिवासी प्राप्तकर्ता के हाथों में आय है या नहीं, क्योंकि अधिनियम की धारा 195 के तहत इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत लागू दरों पर प्रभार्य किसी अन्य राशि पर कटौती की आवश्यकता है। इस प्रकार यह आवश्यकता है कि कटौतीकर्ता को यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि क्या "राशि आयकर अधिनियम के तहत प्रभार्य है"। "प्रचलित दर" शब्द को अधिनियम की धारा 2 के खंड (37ए) में परिभाषित किया गया है और यह अधिनियम की धारा 90 या धारा 90ए के तहत समझौते का लाभ देता है। यदि पात्र है, तो स्रोत पर कर की कटौती की जाने वाली दर की दर निर्धारित करने में। इसलिए, यह जांचने की और आवश्यकता है कि क्या राशि कर संधि के तहत कर योग्य है और यदि हाँ, तो किस दर पर। अधिनियम की धारा 194द में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस धारा में ये दो शब्द नहीं हैं। इसलिए, कटौतीकर्ता के

लिए यह सत्यापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि प्राप्तकर्ता के हाथों में राशि कर योग्य है या नहीं या वह धारा जिसके तहत यह कर योग्य है।

यह भी रेखांकित किया जा सकता है कि ये दो शब्द अधिनियम की धारा 194ई में भी नहीं हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पीआईएलसीओएम बनाम सीआईटी पश्चिम बंगाल (सिविल अपील संख्या 5749/2012) के मामले में यह माना है कि अधिनियम की धारा 194ई के तहत कर की कटौती उसमें दर्शाई गई विशिष्ट दर पर की जानी है और गैर-निवासी के हाथों में कर देयता या कर देयता की दर को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 2. क्या यह आवश्यक है कि अधिनियम की धारा 194द के संचालन के लिए लाभ या अनुलाभ वस्तु के रूप में होना चाहिए?

उत्तर: अधिनियम की धारा 194द के तहत कर की कटौती की जानी आवश्यक है, चाहे लाभ या अनुलाभ नकद में हो या वस्तु के रूप में। इस संबंध में अधिनियम की धारा 194द की उपधारा (1) के प्रथम प्रावधान की ओर ध्यान आकर्षित करना महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है:

"बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां लाभ या अनुलाभ, जैसा भी मामला हो, पूर्णतः वस्तु के रूप में या अंशतः नकद में हो और अंशतः वस्तु के रूप में हो, किन्तु नकद में ऐसा भाग ऐसे संपूर्ण लाभ या अनुलाभ के संबंध में कर की कटौती के दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो, वहां ऐसे लाभ या अनुलाभ को प्रदान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को लाभ या अनुलाभ को वापस लेने/देने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि कटौती किए जाने वाले कर का भुगतान लाभ या अनुलाभ के संबंध में कर दिया गया है:"

यह प्रावधान स्पष्ट रूप से विधानमंडल की मंशा को दर्शाता है कि ऐसी स्थितियाँ भी हो सकती हैं जहाँ लाभ या अनुलाभ नकद में हो या लाभ या अनुलाभ वस्तु के रूप में हो या आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में हो। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 194द स्पष्ट रूप से उस स्थिति को अपने दायरे में लाती है जहाँ लाभ या अनुलाभ नकद या वस्तु के रूप में हो या आंशिक रूप से नकद या आंशिक रूप से वस्तु के रूप में हो।

प्रश्न 3. क्या अधिनियम की धारा 194द के तहत कर कटौती की कोई आवश्यकता है, जब लाभ या अनुलाभ पूंजीगत संपत्ति के रूप में हो?

उत्तर: जैसा कि प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में कहा गया है, यह जाँचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्या अनुलाभ या लाभ प्राप्तकर्ता के हाथों में कर योग्य है और किस धारा के तहत यह कर योग्य है।

इसके अलावा, न्यायालयों ने कई लाभों या अनुलाभों को कर योग्य माना है, भले ही कोई यह तर्क दे सकता है कि वे पूंजीगत संपत्ति की प्रकृति के हैं। निम्नलिखित निर्णय इस बिंदु को स्पष्ट करते हैं:

करदाता ने भूमि के एक भूखंड की खरीद के लिए 'जे' के साथ एक समझौता किया और बयाना राशि के रूप में कुछ राशि का भुगतान किया। हालांकि, भूमि का कब्जा करदाता को नहीं दिया गया और विक्रेता ने उक्त भूखंड को विकसित करने के लिए तीसरे पक्ष के साथ एक और समझौता किया। करदाता ने मुकदमा दायर किया जिसमें एक सहमति डिक्री पारित की गई और उसी के अनुसरण में करदाता को कुछ राशि का भुगतान किया गया। अपील पर यह माना गया कि सहमति डिक्री के अनुसरण में प्राप्त ऐसी राशि धारा 28 (iv) के तहत व्यावसायिक आय के रूप में कर योग्य थी। रमेश बाबूलाल शाह बनाम सीआईटी [2015] 53 taxmann.com 277 (Bom.)

एकमुश्त निपटान योजना के तहत बैंक द्वारा माफ किए गए मूल ऋण का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि धारा 28 (iv) के तहत आने वाली आय का गठन करेगी जो व्यवसाय या पेशे के अभ्यास से उत्पन्न किसी भी लाभ या अनुलाभ के मूल्य से संबंधित है। सीआईटी बनाम रामनियम होम्स (पी) लिमिटेड [2016] 68 taxmann.com 289 (Mad.)

निदेशक को दिए गए किराए के बिना आवास, फर्नीचर और फिक्स्चर का मूल्य धारा 28 (iv) के तहत कर योग्य माना गया। सीआईटी बनाम सुब्रत रॉय [2016] 385 आईटीआर 547 (All)

जहां एक कार एक करदाता को उसके शिष्य द्वारा दी गई थी, जिसे उसके उपदेश से लाभ हुआ था, कार का मूल्य करदाता के हाथों में कर योग्य माना गया क्योंकि यह उसके द्वारा किए गए व्यवसाय के अभ्यास से प्राप्त रसीद थी। सीआईटी (अतिरिक्त) बनाम राम कृपाल त्रिपाठी [1980] 125 आईटीआर 408 (All.)

करदाता एक कंपनी का निदेशक था। प्रमोटर्स के साथ एक समझौते के अनुसार, निदेशक को शेयर आवंटित किए गए थे। इन तथ्यों पर, यह माना गया कि निदेशक द्वारा प्राप्त शेयर निदेशक द्वारा कंपनी से प्राप्त लाभ या अनुलाभ थे और यह कर के लिए कर योग्य लाभ था। डी. एम. नेटरवाला बनाम सीआईटी [1986] 122 आईटीआर 880 (Bom.)। भूमि के उपहार का मूल्य करदाता द्वारा अपने व्यवसाय को जारी रखने के लिए रसीद के रूप में माना जाता था और इसे कर योग्य माना जाता था। अमरेंद्र नाथ चक्रवर्ती बनाम सीआईटी [1971] 79 आईटीआर 342 (Cal.)

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि लाभ या अनुलाभ के रूप में दी गई संपत्ति कार, भूमि आदि जैसे शब्द के सामान्य अर्थ में पूंजीगत संपत्ति हो सकती है, लेकिन प्राप्तकर्ता के हाथों में यह लाभ या अनुलाभ है और तदनुसार इसे कर योग्य माना गया है। किसी भी मामले में, जैसा कि पहले कहा गया है, कटौतीकर्ता को यह जांचने की आवश्यकता नहीं है कि लाभ या अनुलाभ प्राप्तकर्ता के हाथों में कर योग्य है या नहीं। इस प्रकार, कटौतीकर्ता को उन सभी मामलों में अधिनियम की धारा 194द के तहत कर में कटौती करने की आवश्यकता होती है, जहाँ लाभ या अनुलाभ (किसी भी प्रकृति का) प्रदान किया जाता है।

प्रश्न 4: क्या बिक्री छूट, नकद छूट और छूट लाभ या अनुलाभ हैं?

उत्तर: सूचीबद्ध खुदरा मूल्य से ग्राहकों को दी जाने वाली बिक्री छूट, नकद छूट या छूट स्वयं बिक्री मूल्य की कम प्राप्ति को दर्शाती हैं। उस सीमा तक खरीद मूल्य या ग्राहक भी कम हो जाता है। तार्किक रूप से ये भी लाभ हैं, हालांकि बिक्री/खरीद से संबंधित हैं। चूंकि अधिनियम की धारा 194द के तहत टीडीएस सभी प्रकार के लाभ/अनुलाभ पर लागू है, इसलिए कर काटा जाना आवश्यक है। हालांकि, यह देखा गया है कि इन्हें कर कटौती के अधीन करने से विक्रेता को कठिनाई होगी। ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि बिक्री छूट, नकद छूट और ग्राहकों को दी जाने वाली छूट पर अधिनियम की धारा 194द के तहत कोई कर काटने की आवश्यकता नहीं है। एक और स्थिति हो सकती है, जहां एक विक्रेता अपने स्टॉक से अपने सामान को खरीदार को बेच रहा है। विक्रेता 10 वस्तुओं की खरीद पर दो वस्तुएं मुफ्त देता है। मूलतः, विक्रेता वास्तव में 10 वस्तुओं की कीमत पर 12 वस्तुएं बेच रहा है। आइए हम मान लें कि प्रत्येक वस्तु की कीमत 12 रुपये है। इस मामले में, विक्रेता के लिए विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के लिए 120 रुपये होगा। ऐसी स्थिति में, धारा 194द के प्रावधान को लागू करने में फिर से कठिनाई हो सकती है। इसलिए, कठिनाई को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों पर अधिनियम की धारा 194द के तहत कोई कर कटौती करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि जब निःशुल्क नमूने दिए जाते हैं तो स्थिति अलग होती है और उपरोक्त छूट निःशुल्क नमूनों की स्थिति पर लागू नहीं होगी।

इसी तरह, यह छूट विक्रेता द्वारा अपनी बिक्री के संबंध में प्रदान किए जाने वाले अन्य लाभों पर लागू नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित कुछ ऐसे लाभों/सुविधाओं के उदाहरण हैं जिन पर अधिनियम की धारा 194द के तहत कर कटौती की जानी आवश्यक है (सूची संपूर्ण नहीं है):

जब कोई व्यक्ति नकद या वस्तु के रूप में प्रोत्साहन (छूट, छूट के अलावा) देता है जैसे कि कार, टीवी, कंप्यूटर, सोने का सिक्का, मोबाइल फोन आदि।

जब कोई व्यक्ति कुछ लक्ष्य प्राप्त करने पर प्राप्तकर्ता और उसके रिश्तेदारों के लिए यात्रा प्रायोजित करता है

जब कोई व्यक्ति किसी कार्यक्रम के लिए मुफ्त टिकट प्रदान करता है

जब कोई व्यक्ति चिकित्सकों को दवा के नमूने मुफ्त देता है।

उपरोक्त उदाहरण केवल उदाहरण हैं। बिक्री छूट और छूट के लिए कर की कटौती न करने से दी गई छूट केवल उन्हीं वस्तुओं पर है और इसे अन्य पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इन लाभों/अनुलाभों का उपयोग प्राप्तकर्ता इकाई के मालिक/निदेशक/कर्मचारी या उनके रिश्तेदारों द्वारा किया जा सकता है, जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में व्यवसाय नहीं कर रहे हैं या कोई पेशा नहीं अपना रहे हैं। हालांकि, कर को प्राप्तकर्ता इकाई के नाम पर व्यक्ति द्वारा काटा जाना आवश्यक है क्योंकि मालिक/निदेशक/कर्मचारी/रिश्तेदार द्वारा उपयोग प्राप्तकर्ता इकाई के साथ उनके संबंध के आधार पर है और वास्तव में लाभ/अनुलाभ व्यक्ति द्वारा प्राप्तकर्ता इकाई को प्रदान किया गया है।

उदाहरण के लिए, किसी कंपनी द्वारा किसी डॉक्टर को निःशुल्क दवा का नमूना प्रदान किया जा सकता है जो किसी अस्पताल का कर्मचारी है। अधिनियम की धारा 194द के तहत टीडीएस कंपनी द्वारा अस्पताल के हाथों में काटा जाना आवश्यक है क्योंकि डॉक्टर को अस्पताल का कर्मचारी होने के कारण लाभ/अनुलाभ प्रदान किया जाता है। इस प्रकार, मूल रूप से, लाभ/अनुलाभ अस्पताल को प्रदान किया जाता है। अस्पताल बाद में इस लाभ/अनुलाभ को अधिनियम की धारा 17 के तहत अपने कर्मचारियों (यदि इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति उसका कर्मचारी है) को दिए गए अनुलाभ के रूप में मान सकता है और अधिनियम की धारा 192 के तहत कर काट सकता है। ऐसे मामले में यह पहले अस्पताल के हाथों में कर योग्य होगा और फिर वेतन व्यय के रूप में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार, अंततः राशि कर्मचारी के हाथों में कर के रूप में आएगी न कि अस्पताल के हाथों में। अस्पताल अपना कर रिटर्न प्रस्तुत करके अधिनियम की धारा 194द के तहत काटे गए कर का क्रेडिट प्राप्त कर सकता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम की धारा 194द की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में बीस हजार रुपए की सीमा को प्राप्तकर्ता इकाई के संबंध में भी देखा जाना अपेक्षित है।

इसी तरह, यदि लाभ या अनुलाभ किसी डॉक्टर को प्रदान किया जाता है जो अस्पताल में परामर्शदाता के रूप में काम कर रहा है, तो अधिनियम की धारा 194द के तहत कर काटा जाना आवश्यक है। इस मामले में लाभ या अनुलाभ प्रदाता अस्पताल को प्राप्तकर्ता के रूप में अधिनियम की धारा 194द के तहत कर काट सकता है और फिर अस्पताल परामर्शदाता को वही लाभ या अनुलाभ प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 194द के तहत फिर से कर काट सकता है। कठिनाई को दूर करने के लिए, वैकल्पिक रूप से, मूल लाभ या अनुलाभ प्रदाता प्राप्तकर्ता के रूप में परामर्शदाता के मामले में अधिनियम की धारा 194द के तहत सीधे कर काट सकता है। अधिनियम की धारा 194द का प्रावधान लागू नहीं होगा यदि लाभ या अनुलाभ किसी सरकारी संस्था, जैसे सरकारी अस्पताल को प्रदान किया जा रहा है, जो व्यवसाय या पेशा नहीं चला रहा है।

प्रश्न 5. लाभ/अनुलाभ का मूल्यांकन कैसे किया जाना आवश्यक है? उत्तर: मूल्यांकन निम्नलिखित मामलों को छोड़कर लाभ या अनुलाभ के उचित बाजार मूल्य पर आधारित होगा: -

(i) लाभ/अनुलाभ प्रदाता ने प्राप्तकर्ता को प्रदान करने से पहले लाभ/अनुलाभ खरीदा है। उस स्थिति में क्रय मूल्य ऐसे लाभ/अनुलाभ का मूल्य होगा।

(ii) लाभ/अनुलाभ प्रदाता लाभ/अनुलाभ के रूप में दी गई ऐसी वस्तुओं का निर्माण करता है, तो ऐसी वस्तुओं उत्तर: कोई भी व्यय जो व्यवसाय या पेशे को चलाने वाले व्यक्ति का दायित्व है, यदि दूसरे व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाता है तो वह वास्तव में व्यवसाय/पेशे के दौरान दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले व्यक्ति को प्रदान किया गया लाभ/अनुलाभ है।

के लिए वह अपने ग्राहकों से जो कीमत वसूलता है, वह ऐसे लाभ/अनुलाभ का मूल्य होगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम की धारा 194द के तहत टीडीएस के लिए लाभ/अनुलाभ के मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए जीएसटी को शामिल नहीं किया जाएगा।

प्रश्न 6: कई बार, किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को किसी विनिर्माण कंपनी का उत्पाद दिया जाता है ताकि वह उस उत्पाद का उपयोग कर सके और सोशल मीडिया में उस उत्पाद के बारे में बोलने के लिए ऑडियो/वीडियो बना सके। क्या ऐसे इन्फ्लुएंसर को दिया गया यह उत्पाद कोई लाभ या अनुलाभ है?

उत्तर: यह लाभ है या अनुलाभ, यह मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। यदि लाभ या अनुलाभ कार, मोबाइल, पोशाक, सौंदर्य प्रसाधन आदि जैसे उत्पाद हैं और यदि उत्पाद को सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से उपयोग करने के बाद निर्माता कंपनी को वापस कर दिया जाता है, तो इसे अधिनियम की धारा 194द के प्रयोजनों के लिए लाभ/अनुलाभ नहीं माना जाएगा। हालाँकि, यदि उत्पाद को बरकरार रखा जाता है तो यह लाभ/अनुलाभ की प्रकृति का होगा और अधिनियम की धारा 194द के तहत तदनुसार कर काटा जाना आवश्यक है।

प्रश्न 7: क्या सेवा प्रदान करने के दौरान सेवा प्रदाता द्वारा किए गए जेब से किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति लाभ/अनुलाभ है?

मान लीजिए कि एक सलाहकार किसी व्यक्ति "X" को सेवा प्रदान कर रहा है जिसके लिए उसे परामर्श शुल्क मिल रहा है। उस सेवा को प्रदान करने के दौरान, उसे उस स्थान से अलग शहर की यात्रा करनी पड़ती है जहाँ वह नियमित रूप से व्यवसाय या पेशा करता है। इस उद्देश्य के लिए, वह "X" को सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किए गए बोर्डिंग और लॉजिंग व्यय का भुगतान करता है। आम तौर पर, सलाहकार द्वारा किया गया व्यय उसके व्यवसाय व्यय का हिस्सा होता है जिसे कंपनी "X" से प्राप्त शुल्क से घटाया जा सकता है। ऐसे मामले में, सलाहकार द्वारा प्राप्त शुल्क उसकी आय है और यात्रा पर किया गया व्यय उसकी कुल आय की गणना में ऐसी आय से घटाया जाने वाला व्यय है। अब यदि यह यात्रा व्यय कंपनी "X" द्वारा वहन किया जाता है, तो यह सलाहकार को "X" द्वारा प्रदान किया गया लाभ या अनुलाभ है।

हालाँकि, कभी-कभी चालान "X" के नाम से प्राप्त किया जाता है और तदनुसार, यदि सलाहकार द्वारा भुगतान किया जाता है, तो "X" द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। इस मामले में, चूंकि सलाहकार द्वारा भुगतान किया गया व्यय (जिसके लिए प्रतिपूर्ति की जाती है) पूरी तरह से और विशेष रूप से "X" को सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है और चालान "X" के नाम पर है, इसलिए सेवा प्राप्तकर्ता होने के नाते "X" द्वारा की गई प्रतिपूर्ति को अधिनियम की धारा 194द के प्रयोजनों के लिए लाभ/अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाएगा।

यदि चालान "X" के नाम पर नहीं है और भुगतान "X" द्वारा सीधे किया जाता है या प्रतिपूर्ति की जाती है, तो यह "X" द्वारा सलाहकार को प्रदान किया गया लाभ/अनुलाभ है जिसके लिए अधिनियम की धारा 194द के तहत कटौती की जानी आवश्यक है।

प्रश्न 8: यदि कंपनी के उत्पादों के बारे में डीलरों को शिक्षित करने के लिए डीलर सम्मेलन होता है - क्या यह लाभ/अनुलाभ है?

उत्तर: डीलर/व्यवसाय सम्मेलन से संबंधित व्यय को अधिनियम की धारा 194द के प्रयोजनों के लिए लाभ/अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाएगा, जब डीलर/व्यवसाय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य डीलरों/ग्राहकों को निम्नलिखित या समान पहलुओं के बारे में शिक्षित करना हो:

- (i) नया उत्पाद लॉन्च किया जाना
- (ii) इस बात पर चर्चा कि उत्पाद दूसरों से कैसे बेहतर है
- (iii) डीलरों/ग्राहकों से ऑर्डर प्राप्त करना
- (iv) डीलरों/ग्राहकों को बिक्री तकनीक सिखाना
- (v) डीलरों/ग्राहकों के प्रश्नों का समाधान करना
- (vi) डीलरों/ग्राहकों के साथ खातों का समाधान करना

हालाँकि, इस तरह के सम्मेलन का उद्देश्य उन चुनिंदा डीलरों/ग्राहकों को प्रोत्साहन/लाभ देना नहीं होना चाहिए जिन्होंने विशेष लक्ष्य हासिल कर लिए हैं।

इसके अलावा, निम्नलिखित मामलों में व्यय को अधिनियम की धारा 194द के प्रयोजनों के लिए लाभ या अनुलाभ के रूप में माना जाएगा: - (i) अवकाश यात्रा या अवकाश घटक के कारण व्यय, भले ही यह डीलर/व्यावसायिक सम्मेलन के लिए आकस्मिक हो। (ii) डीलर/व्यावसायिक सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति के साथ आए परिवार के सदस्यों के लिए किया गया व्यय (iii) डीलर/व्यावसायिक सम्मेलन में भाग लेने वालों पर उन दिनों के लिए व्यय जो ऐसे सम्मेलन की तिथियों से परे पूर्व प्रवास या अधिक प्रवास के कारण हैं।

प्रश्न 9: धारा 194द में प्रावधान है कि यदि लाभ/अनुलाभ वस्तु के रूप में या आंशिक रूप से वस्तु के रूप में है (और नकद टीडीएस को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है) तो ऐसे लाभ या अनुलाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि लाभ या अनुलाभ जारी करने से पहले, कटौती किए जाने वाले कर का भुगतान लाभ या अनुलाभ के संबंध में किया गया है। ऐसा व्यक्ति कैसे संतुष्ट हो सकता है कि कर जमा कर दिया गया है?

वैकल्पिक रूप से, यदि कोई कठिनाई हो तो उसे दूर करने के विकल्प के रूप में, लाभ प्रदाता अधिनियम की धारा 194द के तहत कर काट सकता है और सरकार को भुगतान कर सकता है। कर की कटौती इस तथ्य को ध्यान में रखने के बाद की जानी चाहिए कि उसके द्वारा टीडीएस के रूप में भुगतान किया गया कर भी अधिनियम की धारा 194द के तहत एक लाभ है। फॉर्म 26क्यू में उसे इसे प्रदान किए गए लाभ पर काटे गए कर के रूप में दिखाना होगा।

प्रश्न 10. धारा 194द 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी होगी। अधिनियम की धारा 194द की उप-धारा (1) का दूसरा प्रावधान यह प्रावधान करता है कि इस धारा का प्रावधान वहां लागू नहीं होता है जहां वित्तीय वर्ष के दौरान किसी निवासी को प्रदान किए गए या प्रदान किए जाने वाले लाभ या अनुलाभ का मूल्य या कुल मूल्य बीस हजार रुपये से अधिक नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बीस हजार की इस सीमा की गणना कैसे की जाएगी?

उत्तर: इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि, -

(i) चूंकि बीस हजार रुपये की सीमा वित्तीय वर्ष के संबंध में है, इसलिए अधिनियम की धारा 194द के तहत कटौती को ट्रिगर करने वाले लाभ या अनुलाभ के मूल्य या कुल मूल्य की गणना 1 अप्रैल, 2022 से की जाएगी। इसलिए, यदि किसी निवासी को प्रदान किए गए या प्रदान किए जाने वाले लाभ या अनुलाभ का मूल्य या कुल मूल्य वित्तीय वर्ष 2022-23 (30 जून, 2022 तक की अवधि सहित) के दौरान बीस हजार रुपये से अधिक है, तो धारा 194द का प्रावधान 1 जुलाई 2022 को या उसके बाद प्रदान किए गए किसी भी लाभ या अनुलाभ पर लागू होगा।

(ii) 30 जून 2022 को या उससे पहले प्रदान किया गया लाभ या अनुलाभ अधिनियम की धारा 194द के तहत कर कटौती के अधीन नहीं होगा।

(अंकित जैन)

भारत सरकार के अवर सचिव